पुलिस अफसर सोमपाल सिंह के सामने....

पेज एक का शेष

लिए कहा। शेखर ने इस पर आपत्ति जताई तो उसने शेखर को धमकी दी। उसी दौरान वहां एनएच 3 के चौकी इंचार्ज सोमपाल सिंह आ पहुंचे। पत्रकार शेखर ने उनसे उस गुंडे की शिकायत की। चौकी इंचार्ज ने उस गुंडे को कुछ नहीं कहा। इस पर उसकी हिम्मत और बढ़ी। उसने चौकी इंचार्ज सोमपाल के सामने ही पत्रकार शेखर को थप्पड़ मारने की बात फिर से दोहरा दी और आरोप लगाने लगा कि आप इस घटना को लाइव करके जनता को भड़का रहे हो। पत्रकार शेखर दास ने जब चौकी इंचार्ज सोमपाल से कार्रवाई के लिए कहा तो सोमपाल ने कहा कि वो तो आप पर जनता को भड़काने का आरोप लगा रहा है। इस पर शेखर ने कहा कि आप पूरी वीडियो रेकॉर्डिंग देख लो। तब सोमपाल ने कहा आप लिखित शिकायत दो। हालांकि चौकी इंचार्ज का अपने सामने हुई घटना की लिखित शिकायत मांगना ड्यूटी में घोर लापरवाही और गुंडा तत्व का खुला समर्थन करने का सबूत है जो वीडियो में कैद है। चौकी इंचार्ज के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने अपने कर्तव्य में इतना बड़ी लापरवाही कैसे बरती। पाठकों से निवेदन है कि फेसबुक पर मजदूर मोर्चा के पेज पर जाकर उस वीडियो को पूरा देंखे और इन पुलिसकर्मियों की कारगुजारी का अंदाजा लगायें।

मजदूर मोर्चा के संपादक ने इस संबंध में 20 अप्रैल को ही फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओ.पी. सिंह को ईमेल भेजकर इस घटना की जानकारी दी और संबंधित पुलिसकर्मियों और उस गुंडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन इस समाचार के लिखे जाने तक पुलिस कमिश्नर ने उस ईमेल का जवाब नहीं दिया है।

सख्ती की आड़ में नोट छापने का धंधा

हरियाणा सरकार ने पुलिस को मास्क न लगाने वालों का चालान करने को सख्ती से कहा था। लेकिन पुलिस ने इस आपदा में अवसर तलाश लिया है। अब वो मास्क लगाए हुए भी लोगों की गाड़ियां इस ढंग से रोक रहे हैं कि कई बार हादसा होने का खतरा रहता है। कई बार तो पुलिसकर्मी ही गाड़ी की पहिए के नीचे आते-आते

बचे। वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न नियम तोड़ने पर राशि बहुत ज्यादा हो चुकी है। वाहन के रुकते ही ज्यादातर पुलिस वाले चालान काटने की बजाय लेन-देन की बात शुरू कर देते हैं। चालक को इतना डरा दिया जाता है कि वह पांच सौ रुपये देकर जान छुड़ा लेता है। वाहन चालक किसी भी आफेंस पर रोका गया हो, उसे मास्क न पहनने का ही पांच सौ रुपये का चालान थमाया जाता है। सबसे कम जुर्माना इसी मद में है। जो लोग कोर्ट चालान की मांग करते हैं, पुलिस उनसे उलझने की कोशिश करती है। उसमें चालान करने वाले पुलिसकर्मी को घाटा हो जाता है। कोराना काल से पहले पुलिस फरीदाबाद के विभिन्न चौराहों पर खड़े होकर चालान काट रही थी। लेकिन जब से सरकार ने सख्ती को कहा तो उसने चौराहे छोड़कर उसके आगे पीछे चालान काटने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि पुलिसकर्मियों की हरकत चौराहों पर लगे सीसीटीवी में रेकॉर्ड न हो सके। फरीदाबाद पुलिस बिना बैरिकेडिंग किए इन दिनों जिस तरह चालान काट रही है, वह नियम विरुद्ध तो है ही, साथ ही वह पुलिसकर्मियों की जान को जोखिम में डालना भी है। विगत में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब पुलिसकर्मी को कुचलकर वाहन चले जाते हैं। कुछ पुलिसकर्मी डंडा फेंककर जिस तरह दोपहिया वाहनों को रोकते हैं, वह भी खतरनाक है। इससे वाहन चालक के गिरने और मरने का खतरा होता है।

इस सारे मामले में आला पुलिस अफसरों की चुप्पी फरीदाबाद के पुलिसकर्मियों का मनोबल गलत तरीके से बढ़ा रही है। शहर की जनता में इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। वाहन अधिनियम तोड़ने वालों का चालान बेहद जरूरी है लेकिन वह बिना काली कमाई किए बिना भी हो सकता है।

वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध नहीं

आरटीआई एक्टिविस्ट अजय बहल ने हाल ही में एक आरटीआई के जरिए मांग की थी फरीदाबाद समेत हरियाणा में सभी शहरों-गांवों की पुलिस जो चालान वाहन अधिनियम के तहत कर रही है, उसकी जानकारी रोजाना पुलिस की वेबसाइट पर दी जाए। अजय बहल की आरटीआई के हक में फैसला सुनाते हुए हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल ने आदेश दिया कि पुलिस को रोजाना ऐसे चालान की जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी ही होगी। सिंघल ने यह भी सुझाव दिया था कि पुलिस चाहे तो इस काम के लिए अलग से भी अपनी वेबसाइट बना सकती है, जहां यह जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाए। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर जो इंटरनेट फ्रेंडली माने जाते हैं, अभी तक ऐसी सूचना अपने मातहत कर्मचारियों से रोजाना अपलोड करवाना शुरू नहीं करा सके। फरीदाबाद की जनता को तमाम चोर, उचक्कों, उठाईगीरों के पकड़े जाने की सूचना पुलिस अपने प्रेसनोट के जरिए मीडिया में प्रकाशित कराती रहती है लेकिन वाहनों के चालान की सूचना अपलोड नहीं कराई जा रही है।

सवाल यह है कि आखिर आरटीआई एक्टिविस्ट अजय बहल ने इस मामले को क्यों उठाया। अजय बहल का कहना है कि पुलिसवालों के हाथ में एक मशीन होती है, जिसके जरिए वह चालान किए गए वाहन चालक से पैसे लेकर रसीद दे देती है। बहल का कहना है कि तमाम जगहों पर असामाजिक तत्व या साइबर अपराधी पुलिस की ड्रेस पहनकर ऐसी मशीन लेकर लोगों का फर्जी चालान काटकर अवैध पैसे कमा सकते हैं। एक तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर चालान अपलोड होगा तो वाहन चालक यह भी जानेगा कि किस थाने या चौकी की पुलिस ने चालान काटा है। नाम रेकॉर्ड में आने से डरकर वह वाहन अधिनियम आगे से तोड़ने में हिचकेगा। चालान अपलोड करना पुलिस के हित में है।

20-20 दिनों में किसानों को टुकड़ों में मिल रहे हैं फसल के पैसे

खट्टर सरकार कर रही है 72 घंटों में भुगतान का दावा, जमीनी हकीकत आकर देखें सीएम

चन्द्र प्रकाश

बल्लभगढ़: किसानों की उनकी फसल का भुगतान 72 घंटों में करने का खट्टर सरकार दावा खोखला साबित हो रहा है। किसानों को तीन दिन से लेकर एक-एक हफ्ते में पैसे किस्तों में मिल रहे हैं। छोटी-छोटी राशि किस्तों में आने की वजह से किसान आगे की फसल की योजना भी नहीं बना पा रहे हैं। अपना फसल अपना ब्यौरा पोर्टल पर आनलाइन सूचना भरने ने भी किसान की सिरदर्दी बढ़ा दी है। आनलाइन सिस्टम को किसान पसंद नहीं कर रहा है। इस संवाददाता ने बल्लभगढ़ और आसपास की मंडियों और गांवों में दौरा कर हालात का जायजा लिया। मोहना, फतेहपुर, और बल्लभगढ़ मंडी में गेहूं की आवक जोरों पर है। किसान जल्द से जल्द अपना गेहूं मंडी में ला रहा है। सरकारी खरीद बंद होने से पहले वह एमएसपी. पर खरीद का लाभ नहीं छोड़ना चाहता।

बीस दिन में आ रहे हैं पैसे

बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसान किरपाल ने बताया कि उन्होंने एक हजार क्विंटल गेहूं अनाज मंडी में पहुंचाया। खट्टर सरकार ने तीन दिन बाद उनके खाते में 500 क्विंटल के पैसे डाल दिए। उसके तीन दिन बाद 200 क्विंटल के पैसे डाले। फिर तीन बाद बकाया राशि खाते में डाली गई। किसान ने एकमुश्त मंडी में अपना अनाज बेचा लेकिन उसे पैसा छोटी किस्तों में मिला। छोटे और मध्यम किसान सरकार की इस नई नीति से परेशान हैं। हां, कुछ बड़े जमींदारों ने सरकार की इस योजना की सराहना जरूर की। गांव जवां के किसान भानु प्रकाश मलिक भी सरकार की इस नई खरीद पॉलिसी का समर्थन करते हैं लेकिन आज 25 दिन हो गए उन्हें मंडी में अपना गेहूं बेचे, पैसे अभी तक उनके खाते में नहीं आए हैं। किसी किसान के 10 दिन में, किसी के 20 दिन में पैसे आ रहे हैं। हरियाणा सरकार का 72 घंटे में किसान को भुगतान का वादा पूरा नहीं हुआ और सरकार स्वयं अपनी पीठ ठोंक कर किसान हितैषी होने का बेहूदा प्रचार कर रही है।

आढ़ती का कमीशन नहीं बदला

इस बार पैसा बेशक सरकार सीधे किसानों के खाते में डाल रही है। लेकिन आढ़ती का कमीशन पहले भी ढाई फीसदी था और आज भी उतना ही मिल रहा है। पहले जो पैसा आढ़ती के खाते में आता फिर वह किसान की पेमेंट करता, अब वही पैसा सीधा किसान के खाते में पहुंचा कर सरकार ने किसानों को कौन सा तोहफा दे दिया है, समझ में नहीं आता। सरकार किसान को सस्ती दरों पर कर्ज देती तो समझ में आता, उसकी माली हालत में सुधार लाती तो समझ में आता, उसका कर्ज माफ करती तो समझ में आता। बिजली की बढ़ती यूनिटों को कम करती, खाद, बीज, दवाई की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाती तो समझ में आता। सरकार की इस जुमलेबाजी को किसान कब समझेगा?

आढ़ती किसान का शोषण तब करता है, जब सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं करती है। हरियाणा में तो गेहूं की खरीद एमएसपी पर होती है लेकिन धान, बाजरा, ज्वार आदि की खरीद एमएसपी पर नहीं की जाती, जिसमें आढ़ती प्राइवेट खरीदार के साथ मिलकर कमीशनखोरी करता है। नये कृषि कानूनों के विरोध का मुख्य मुद्दा भी यही है कि किसान की 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारण के बाद भी सरकार उसे एमएसपी पर नही खरीदती है।

हालात का मारा किसान

जो किसान पूरी तरह अपनी खेती पर आधारित होता है उसे अपनी गेहूं की फसल तैयार करने में खाद, बीज, दवाई, सिंचाई आदि का खर्च उठाना पड़ता है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है, उसकी कटाई के बाद थ्रेसर, रीपर, कम्बाइन आदि का भुगतान भी करना पड़ता है। क्या ये सेवा देने वाले लोग किसान के खाते में पैसे आने का इंतजार करेंगे, हरगिज नहीं। इन परिस्थितियों में किसान का एकमात्र सहारा आढ़ती ही होता है। सरकार अपनी तरफ से तो किसान को सस्ती दरों पर सहज और सुलभ कर्ज मुहैया कराने में पूरी तरह नाकाम रही है। किसान के प्रति अपनी खोखली हमदर्दी से ही वह आढ़ती प्रथा को खत्म करना चाहती है। लेकिन फिलहाल नाकाम है। आढ़ती को किसान का शोषक कह कर सरकार उसे बदनाम करने का काम भी कर रही है। एमएसपी पर किसान की फसल की खरीद हो, आढ़ती को उसका मेहनताना मिले तो किसान के शोषण होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।

जब फरीदाबाद में शवों का ढेर लगेगा...

पेज एक का शेष

जून 2020 में राहुल सिंह नामक पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन ने इस संवाददाता को बताया था कि स्पेशल रिपेयरिंग के काम का लक्ष्य 6 महीने रखा गया है। यानी रिपेयरिंग के काम को दिसम्बर 2020 में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन यह खबर लिखे जाने के वक्त शुक्रवार 23 अप्रैल 2021 को भी यह मेडिकल कॉलेज कोरोना मरीजों के लिए तैयार नहीं हो पाया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है। उन्होंने एक बार इस अस्पताल के रिपेयर की प्रगति जानने की कोशिश नहीं की। हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो तमाम विवादास्पद विषयों पर ट्वीट करता रहता है, उसने एक बार भी इस मेडिकल कॉलेज की प्रगति के बारे में ट्वीट नहीं किया।

इस अस्पताल को टेकओवर करने के बाद सरकार ने यहां कुछ समय के लिए डॉ गुलशन अरोड़ा को प्रशासक नियुक्त किया था। ये वही डॉ. अरोड़ा है जो बी.के. अस्पताल में सीएमओ रहने के दौरान तमाम मामलों में बदनाम रहा है। जिसमें डॉ. शशि गांधी से जुड़ा मामला भी शामिल रहा है। डॉ. अरोड़ा गोल्ड फील्ड को सुधारने की बजाय अपना सुधार करके यहां से निकल गये। उनके समय में ही सरकार ने इसे खरीदने की प्रक्रिया पूरी की थी।

बहरहाल, कोरोना की दूसरी लहर को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया है। डॉक्टरों ने पिछले साल ही कह दिया था कि दूसरी लहर आयेगी लेकिन जिस तरह मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, ठीक उसी तरह खट्टर, विज और दुष्यंत चौटाला भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अगर छायंसा का मेडिकल कॉलेज कोरोना की दूसरी लहर में काम कर रहा होता तो यहां कम से कम 400-500 कोरोना मरीजों को नई जिन्दगी मिल सकती थी। पिछले साल जब कोरोना फैला था तो खट्टर ने फरीदाबाद में दस हजार बेड के इंतजाम का निर्देश दिया था। क्या खट्टर को अपना निर्देश याद है। क्या जिला प्रशासन बताएगा कि इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है। रोजाना लफ्फाजियों के प्रेस नोट में दावा करके कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के नारे खोखले हो गए।

श्रीराम अस्पताल ही खोल दो

दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में एक अदद बेड और ऑक्सिजन के लिए जहां मारामारी मची है, वहाँ फ़रीदाबाद के तिकोना पार्क का श्रीराम अस्पताल अब भी बंद पड़ा है। इस अस्पताल में 30-35 मरीज़ों का इलाज तो हो ही सकता है। यहाँ तमाम आधुनिक मशीनें भी हैं।इस अस्पताल का इस्तेमाल न तो कोरोना की पहली लहर में हो सका और न ही अब दूसरी लहर में। इस अस्पताल को चलाने वाली सोसाइटी श्रीराम चेरिटेबल सोसाइटी में आपसी झगड़े की वजह से यहाँ ताला लगा हुआ है। इसके अलावा अस्पताल चूँकि नगर निगम फ़रीदाबाद की ज़मीन पर बना है तो उसने इसे अलग से सील कर रखा है।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सोसाइटी के दोनों ग्रुप और अस्पताल के संस्थापक सदस्य तक चाहते हैं कि अस्पताल फिर से शुरू हो लेकिन समझौते की पहल नहीं हो रही है। पंजाबी बिरादरी की अपनी बैठकों में भी मामला सुलझ नहीं सका। मज़दूर मोर्चा इस प्रकरण की खबरें लगातार प्रकाशित कर रहा है।

अस्पताल के संस्थापक सदस्य एस एम हाशमी और स्व बृजमोहन भाटिया के बेटे विशाल भाटिया का कहना है कि अगर सरकार या प्रशासन अस्पताल को अपने नियंत्रण में लेकर संचालित करें तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ कोरोना के गरीब मरीज़ों का इलाज हो। इस मामले में सोसाइटी के निलंबित प्रधान कँवल खत्री रजिस्ट्रार सोसाइटी फ़रीदाबाद और अपने राजनीतिक रसूख़ के ज़रिए मामला हल कराना चाहते हैं। रजिस्ट्रार दफ़्तर में फैले भ्रष्टाचार ने इस मामले को और उलझा दिया है।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. राम खिलावन-बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने 9891164794
6. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
7. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421